नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में आरक्षित

आपराधिक विविध ।आवेदन सं। 2020 का 887

गोल्डी राजीव संथोजी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी

वर्तमानः

श्री त्रिदीप पाई, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अमृतानंद चक्रवर्ती और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अजय नेगी की सहायता से।

श्री J.S। श्री विर्क, उप महाधिवक्ता के साथ श्री ललित मिगलानी, ए. जी. ए. और श्री रोहित ध्यानी, राज्य/प्रतिवादी एन. ओ. एस. के लिए संक्षिप्त धारक। 1,2,4 और 5.

श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री P.C द्वारा सहायता प्राप्त। पेटशाली, प्रतिवादी एन. ओ. एस. के लिए अधिवक्ता ।3.

के साथ

आपराधिक विविध ।आवेदन सं। 2021 का 31

डीडी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी

वर्तमानः

श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री P.C द्वारा सहायता प्राप्त। पेटशाली, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

श्री J.S। श्री विर्क, उप महाधिवक्ता के साथ श्री ललित मिगलानी, ए. जी. ए. और श्री रोहित ध्यानी, राज्य/प्रतिवादी एन. ओ. एस. के लिए संक्षिप्त धारक। 1,2 और 3.

श्री त्रिदीप पाई, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अमृतानंद चक्रवर्ती और श्री अभय नेगी, प्रतिवादी नं.4.

न्याय

प्रति:माननीय रवींद्र मैथानी, जे.

चूंकि, इन दोनों याचिकाओं में (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की खंड 482 के तहत दायर) कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न निहित है, इसलिए उन्हें एक साथ लिया जा रहा है और इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है।

2. इस निर्णय में, पक्षों को संदर्भित किया जाएगा क्योंकि वे आपराधिक विविध श्रेणी में हैं।आवेदन सं। 2020 का 887।तदनुसार, गोल्डी राजीव संथोजी को याचिकाकर्ता और पीड़ितों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो प्रतिवादी नं।इसमें 3 को डीडी ठीक होना में संदर्भित किया जाएगा ताकि उसका नाम छिपाया जा सके।यह ध्यान दिया जा सकता है कि डीडी आपराधिक विविध मामले में याचिकाकर्ता है।आवेदन सं। 2021 का 31.

तथ्य

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में "एसएसपी") उधम सिंह नगर को एक रिपोर्ट मिली थी, जो कथित तौर पर अभिभावक शिक्षक संघ ("पीटीए") बीरशिवा आवासीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिरोलिकलां, किच्छा, जिला उधम सिंह नगर (संक्षेप में, "स्कूल") द्वारा भेजी गई थी। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता स्कूल का प्रबंधक था।उसने छात्रों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और उनसे यह भी कहा कि धमकी के तहत किसी को भी यह न बताए कि अगर यह पता चलता है, तो वह उन्हें व्यावहारिक में विफल कर देगा।रिपोर्ट में अन्य आरोप भी थे।रिपोर्ट शिक्षा विभाग और प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारियों को भी भेजी गई थी।एसएसपी, उधम सिंह नगर ने अपने दिनांकित 19.05.2014 और 23.05.2014 पत्रों द्वारा डॉ. उत्तम सिंह नेगी, सर्कल अधिकारी, सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर (संक्षेप में, "मुखबिर") को मामले में पूछताछ करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।मुखबिर ने मामले की जांच की और याचिकाकर्ता गोल्डी राजीव संथोजी, श्रीमती के बयान दर्ज किए। शकुंतला चौहान, मुरलीधर वैष्णव, K.C। पांडे और जीवन चंद्र उपाध्याय और पांच छात्र, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से पीड़ित किया गया था।सूचना देने वाले ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.07.2014 में निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया; उन्हें अनुचित तरीके से छुआ, लेकिन न तो कोई छात्र और न ही कोई अभिभावक कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए सहमत था।इसलिए, मुखबिर के अनुसार, इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा एक विस्तृत जांच समीचीन होगी।

4. 26.07.2014 की रिपोर्ट, मुखबिर द्वारा एसएसपी, उधम सिंह नगर को प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने निर्देश दिया कि लिखित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जाए।एसएसपी उधम सिंह नगर

आगे निर्देश दिया कि यदि लिखित रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी, तो सूचना देने वाले की 26.07.2014 की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।इसके अनुसार सूचना देने वाले की 26.07.2014 दिनांकित रिपोर्ट को एफ़. आई. आर. नं. भा.दं.सं. सी. की खंड 377,511 के तहत 2015 की खंड 53 और आई. डी. 1 पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, "पॉक्सो अधिनियम") की खंड 10 के साथ पठित खंड 9।जांच पड़ताल की गई।कुछ पीड़ितों से जांच अधिकारी (आई. ओ.) ने पूछताछ की और बयान भी दर्ज किए गए।जाँच के बाद, एक अंतिम रिपोर्ट ("एफ. आर".) प्रस्तुत की गई, जिसे विविध मामले सं. 2019 का 178, डॉ. उत्तम सिंह बनाम गोल्डी राजीव संथोजी, एफटीसी/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर (संक्षेप में, "पहला विविध मामला") की अदालत में।पहले विविध मामले में सूचना देने वाले को जानकारी भेजी गई थी और अदालत द्वारा उसके बयान दर्ज किए गए थे।इसके बाद, 14.1.2019 पर, अदालत ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

5. इसके बाद, डीडी ने एफआर के खिलाफ इस आधार पर एक याचिका दायर की कि वह वर्ष 2012 से 2014 तक स्कूल में छात्र था और प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता गोल्डी राजीव संथोजी स्कूल चला रहे थे।याचिकाकर्ता अपने कमरे में छात्रों के कपड़े उतार देता था और उनके साथ गुदा मैथुन सहित अश्लील गतिविधियाँ करता था और उनका वीडियो भी बनाता था।विरोध याचिका में यह भी कहा गया है कि फरवरी, 2014 के महीने में एक शनिवार को याचिकाकर्ता डीडी और एक और पीड़ित को राम नगर ले गया और वहां पूरी रात उसने पीड़ित के साथ और एक अन्य पीड़ित के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इसकी सूचना एक स्कूल शिक्षक को दी गई, जिन्होंने जब याचिकाकर्ता से इसके बारे में बात की, तो उन्हें स्कूल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।डीडी ने शर्म से स्कूल छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया।जब मामला सामने आया तो पुलिस ने एक बार डीडी से पूछताछ की थी और उससे कहा था कि उसे सबूत दर्ज करने के लिए अदालत द्वारा तलब किया जाएगा, लेकिन उसे कभी तलब नहीं किया गया।अंत में, जब डीडी को बताया गया कि उसने याचिकाकर्ता से पैसे लेने के बाद मामले का निपटारा क्यों किया, तो उसने फाइल का निरीक्षण कराया और विरोध याचिका दायर की।यह विरोध याचिका विविध मामला सं. 2019 का 226, डीडी बनाम गोल्डी राजीव संथोजी ("दूसरा विविध मामला") इस विरोध याचिका पर, <आईडी2> पर, अदालत ने पहले में पारित अपने आदेश दिनांक <आईडी1> को निर्धारित करने से इनकार कर दिया।

विविध मामला, लेकिन विरोध याचिका को शिकायत के रूप में माना और याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. की खंड 377,506 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की खंड 67 और पॉक्सो अधिनियम की खंड <आईडी1> के तहत दंडनीय अपराध के लिए तलब किया।

6. क्रिमिनल मिस्क में।आवेदन सं। 2020 का 887, याचिकाकर्ता ने दूसरे विविध मामले में पारित 15.11.2019 दिनांकित आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसे भा.दं.सं. सी. की खंड 377,506, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की खंड 67 और पॉक्सो अधिनियम की खंड 5/6 के तहत तलब किया गया है।

7. क्रिमिनल मिस्क में।आवेदन सं। 2021 का 31, डीडी ने मामले में आगे की जांच के लिए दूसरे विविध मामले में पारित 15.11.2019 के आदेश को भी चुनौती दी।

<u>आपराधिक विविधता में जवाबी शपथ पत्रआवेदन सं। 2021 का 31</u>

8. राज्य ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया।इसके अनुसार, डीडी द्वारा दायर विरोध याचिका को पहले ही एक कष्ट के रूप में माना जा चुका है और डीडी की कष्ट को सक्षम अदालत द्वारा देखा जा रहा है, इसलिए, संहिता की खंड 482 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं है।राज्य के जवाबी शपथ पत्र के अनुसार, डीडी द्वारा दायर संहिता की खंड 482 के तहत याचिका गुणदोष से रहित है और खारिज होने योग्य है।

9. याचिकाकर्ता ने अपना जवाबी शपथ पत्र भी दाखिल किया।यह काफी विस्तार से बताया गया है।इसके अनुसार, याचिका भ्रामक और गलत है और कानून की गलत समझ पर आधारित है; अस्पष्ट दावे और आधारहीन आरोप और यह संहिता की खंड 482 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।इसलिए, प्रार्थना के अनुसार राहत नहीं दी जानी चाहिए।

10. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

<u>तर्क</u>

<u>याचिकाकर्ता की ओर से</u>

11. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता को बुलाने का यह आदेश दिनांक 15.11.2019 नहीं है।

कानून के अनुसार और इसे अलग रद्दना चाहिए।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क में निम्नलिखित बिंदु उठाए:

(i) रिपोर्ट पर, मुखबिर द्वारा एक जांच की गई थी, जिसे एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया था और यह प्राथमिकी पहली शिकायत है।

(ii) जाँच के बाद, एफ. आर. प्रस्तुत किया गया था, जिसे सूचना देने वाले को सुनने के बाद पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।चूंकि कोई अभिभावक-शिक्षक संघ नहीं था, इसलिए सूचना देने वाले को एफ. आर. की जानकारी दी गई थी।इसके बाद एफ. आर. को स्वीकार कर लिया गया।पीड़ित या उसके रिश्तेदारों को एफ. आर. की जानकारी देने का कोई प्रावधान नहीं है।इसलिए, अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति कानून के अनुसार है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इसलिए, डीडी द्वारा बाद में दायर विरोध याचिका पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता था।

(iii) दूसरी शिकायत में, कुछ परिस्थितियों में संज्ञान लिया जा सकता है, जो तत्काल मामले में मौजूदा नहीं हैं।

(iv) प्रत्येक विरोध याचिका को शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(v) शिकायत के रूप में माने जाने वाले विरोध याचिका में शिकायत की आवश्यकता होनी चाहिए।

(vi) राज्य ने अपने जवाबी शपथ पत्र में एक मुद्दा उठाया है कि डीडी की कष्ट को सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा देखा जा रहा है और एफआर को उचित रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

(vii) प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 जुलाई, 2015 को दाखिल की गई थी और जांच के बाद जब एफ. आर. प्रस्तुत किया गया था, तो इसे <आई. डी. 1> पर स्वीकार कर लिया गया था।

(viii) अपनी विरोध याचिका में, डीडी स्वीकार करता है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन डीडी ने विरोध याचिका दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जब 14.01.2019 पर एफआर पर विचार किया जा रहा था।

(ix) एफ. आर. मिलने के बाद अदालत ने मुखबिर को नोटिस जारी किया और उसका बयान दर्ज किया।इस तरह का बयान कानून के लिए अज्ञात है।सूचना देने वाले डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने कोई विरोध याचिका दायर नहीं की।एफ. आर. मिलने के बाद दर्ज किए गए उनके बयान को विरोध याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(x) एफ. आर. को संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज पीड़ितों के बयानों सहित जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने के बाद स्वीकार किया गया है।संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज किए गए बयान अपनी विश्वसनीयता रखते हैं।

(xi) याचिकाकर्ता को कानून के प्रावधानों के खिलाफ तलब किया गया है।भले ही विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में माना जाना है, लेकिन संज्ञान लेने से पहले संहिता की खंड 200 और 202 के तहत जांच अनिवार्य थी।चूँकि यह तत्काल मामले में नहीं किया गया था, इसलिए दूसरे विविध मामले में याचिकाकर्ता को दिनांक 15.11.2019 पर बुलाने का आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

(xii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

(xiii) डी. डी. द्वारा दायर याचिका खारिज की जा सकती है।

12. उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य के मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा रखा।[1.], (यह तर्क देने के लिए उद्धृत किया गया है कि अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, मजिस्ट्रेट सूचना देने वाले को सुनने के लिए बाध्य है न कि पीड़ित या उसके रिश्तेदारों को और यह भी तर्क देने के लिए कि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, सूचना देने वाले को अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के समय सुना जाता है और किसी अन्य समय नहीं); प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार [2.], महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी और एक अन्य[3.], विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सचिव गृह, नागरिक सचिवालय, लखनऊ और अन्य द्वारा से [4.], अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुखर निंबालकर और एक अन्य [5.] और गंगाधर जनार्दन म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [6.]..

13. वास्तव में, एक बार जब याचिकाकर्ता की ओर से तर्क समाप्त हो गया, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी प्रतिवादीओं की ओर से की गई बहस के जवाब से पहले लिखित तर्क दायर किए।लिखित बहस में निम्नलिखित अतिरिक्त (विरोधाभासी भी) बिंदु उठाए गए हैं:-

[1] (1985) 2 एस. सी. सी. 537
[2] (1962) पूरक (2) एस. सी. आर. 297

[3] (2003) 1 एससीसी 734
[4] (2019) 8 एससीसी 27
[5] (2017) 3 एस. सी. सी. 528
[6] (2004) 7 एससीसी 768

(i) अदालत ने अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सूचना देने वाले का बयान दर्ज करने में कोई अवैधता नहीं की।

(ii) यह मानते हुए कि सूचना देने वाले का बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह FR को अमान्य स्वीकार करते हुए 14.01.2019 दिनांकित आदेश को प्रस्तुत नहीं करता है।

(iii) संभागीय शिक्षा अधिकारी और उप-जिला कलेक्टर द्वारा की गई पूछताछ की अपनी प्रासंगिकता है क्योंकि यह यह व्यवस्थित कानून है कि यदि विभागीय जांच में कोई आरोप साबित नहीं होता है तो आपराधिक मुकदमे में साबित होने की संभावना बहुत कम है।रिलायंस को लोकेश कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य के फैसले में रखा गया है।[7]..

(iv) न्यायालय को केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में जांच में हस्तक्षेप करना चाहिए जहां आदेशिका का दुरुपयोग होता है और संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होता है।रिलायंस को पी. चिदंबरम बनाम के मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय [8] और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली [9]..

(v) डीडी अनिवार्य रूप से आगे की जांच की आड़ में फिर से जांच या नए सिरे से जांच की मांग कर रहा है, लेकिन केवल संवैधानिक अदालतें असाधारण परिस्थितियों में नए सिरे से जांच का आदेश दे सकती हैं।

14. याचिकाकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि डीडी द्वारा दायर संहिता की खंड 482 के तहत याचिका प्रार्थना और सार के संदर्भ में विरोध याचिका से भिन्न है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विरोध याचिका में डीडी द्वारा आगे की जांच की मांग नहीं की गई है।

15. भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "हमारा तदनुसार यह विचार है कि एक ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट को खंड **173** की उप-खंड **(2) (i)** के तहत एक रिपोर्ट भेजी जाती है**,** अपराध का संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को छोड़ने का निर्णय लेता है या यह विचार रखता है कि कोई अपराध नहीं है।

---

[7] (2013) 11 एससीसी 130
[8] (2019) 9 एससीसी 24
[9] (2013) 5 एस. सी. सी. 762

प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार, मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देना चाहिए और रिपोर्ट पर विचार करने के समय उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।

16. माननीय न्यायालय ने आगे कहा, "हम यह भी देख सकते हैं कि भले ही मजिस्ट्रेट घायल व्यक्ति या मृतक के किसी रिश्तेदार को रिपोर्ट पर विचार करने के लिए निर्धारित सुनवाई की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, यदि वह उचित समझता है, तो घायल व्यक्ति या मृतक के किसी विशेष रिश्तेदार या रिश्तेदारों को ऐसी सूचना दे सकता है, लेकिन ऐसी सूचना नहीं देने से उस आदेश पर कोई अमान्य प्रभाव नहीं पड़ेगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने पर दिया जा सकता है।"

17. गंगाधर जनार्दन म्हात्रे (उपरोक्त) के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना देने वाला रिपोर्ट पर विचार करते समय नोटिस और सुनवाई के अवसर का हकदार है।"

18. प्रमथ नाथ तालुकदार (ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

> 50 खंड 202 के तहत जांच का दायरा इन तक सीमित है
> यह निर्धारण के लिए कि आदेशिका जारी की जानी चाहिए या नहीं, शिकायत की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाना और खंड 203 यह निर्धारित करती है कि इस उद्देश्य के लिए किन सामग्रियों ठीक होना विचार किया जाना चाहिए।दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 203 के तहत मजिस्ट्रेट को जो निर्णय देना है, वह शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों और जांच या जांच के परिणाम, यदि कोई हो, पर आधारित होना चाहिए।उसे सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपना निर्णय लेना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।इसलिए यदि उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 202 के तहत की गई जांच के दायरे के बारे में खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया है, और न्यायिक रूप से अपने सामने की सामग्री पर अपना दिमाग लगाया है और फिर अपना आदेश देने के लिए आगे बढ़ता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने गलत तरीके से काम किया है।दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश, हालांकि, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत के मनोरंजन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, जहां पिछला आदेश एक अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से हास्यास्पद तर्क, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते थे, प्रस्तुत किया गए हैं।यह न्यायाधीश के हित में नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ उसके मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद निर्णय दिए जाने के बाद, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को

<u>उसकी शिकायत की जांच करने का एक और मौका</u> दिया गया।अल्लाह दितो बनाम करम बख्श [आई. एल. आर. 12 लाह 9,12]; राम नारायण चौबे बनाम पनाचंद जैन [ए. आई. आर. 1949 पटना 256]
; हंसबाई बनाम आनंद [ए. आई. आर. *1949* बॉम्बे *384]* दोराइसामी बनाम सुब्रमण्यम [ए. आई. आर. 1949 मैड 484]।एक नई शिकायत लाने के लिए नए तथ्यों को प्रस्तुत करने के संबंध में अपील के तहत निर्णय में विशेष पीठ ने उपरोक्त उद्धृत मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय के विचार को प्रतिग्रहण करना नहीं किया और मैक्लीन की राय को अपनाया। रानी महारानी बनाम डोलेगोबिंदा दास *[*आई. एल. आर. 28 कैल 211,216] में द्वारका नाथ मंडल बनाम बेनीमाधास बनर्जी *[(1901)* आई. एल. आर. *28* कैल 652] में एक पूर्ण पीठ द्वारा प्रमाणित गई।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक नई शिकायत पर विचार किया जा सकता है जहां स्पष्ट त्रुटि है, या पिछले आदेश में न्यायाधीश का स्पष्ट गर्भपात है या जब नया सबूत सामने आ रहा है।"

(जोर दिया गया)

19. महेश चंद (ऊपर) के मामले में, प्रमथ नाथ तालुका (ऊपर) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों का पालन किया गया है।

20. विष्णु कुमार तिवारी (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने H.S के मामले में निर्णय का उल्लेख किया। बैन्स बनाम राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़) [10]., जैसा कि नीचे दिया गया है:-

"17. यह न्यायालय H.S में अपने निर्णय के दौरान। बैन्स [H.S। बैन्स बनाम राज्य *(*चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश*), (1980) 4* एस. सी. सी. 631:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 93], निम्नानुसार आयोजित किया गया:(एससीसी पीपी। 634-35, पैरा 6)

.... "..केवल यह तथ्य कि उन्होंने पहले खंड 156 (3) के तहत जांच का आदेश दिया था और खंड 173 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त की थी, शिकायत के पूर्ण उन्मूलन का प्रभाव नहीं होगा और इसलिए मजिस्ट्रेट को खंड 200,203 और 204 के तहत कार्यवाही करने से वर्जिता नहीं जाएगा।इस प्रकार, एक मजिस्ट्रेट जो शिकायत प्राप्त होने पर खंड *156 (3)* के तहत जांच का आदेश देता है और खंड *173 (1)* के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करता है, उसके बाद, तीन में से एक काम कर सकता है:
(1) वह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने और कार्रवाई छोड़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है*; (2)* वह पुलिस रिपोर्ट और जारी करने की प्रक्रिया के आधार पर खंड *190 (1)* (बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है*;* यह वह पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में आए निष्कर्ष से किसी भी तरह से बाध्य हुए बिना कर सकता है*; (3)* वह मूल शिकायत के आधार पर खंड *190 (1) (*ए*)* के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और खंड *200* के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से शपथ लेकर पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ सकता है।यदि वह तीसरा विकल्प अपनाता है, तो वह खंड 202 के तहत जांच कर सकता है या निर्देश दे सकता है यदि वह उचित समझता है।इसके बाद वह शिकायत या जारी करने की आदेशिका को खारिज कर सकता है, जैसा भी मामला हो।"" ""

21. अभिजीत पवार (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की खंड 202 के दायरे पर चर्चा की, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है, जिसमें मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और जैसा कि यहाँ नीचे कहा गया है:-

[10] (1980) 4 एस. सी. सी. 631

> "23. कानून में स्वीकार की गई स्थिति यह है कि उन मामलों में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, मजिस्ट्रेट की ओर से आदेशिका जारी करने से पहले जांच या जांच करना अनिवार्य है।दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा वर्ष 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा खंड 202 में संशोधन किया गया था, जिसमें शब्द जोड़े गए थे "और ऐसे मामले में जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।"इस संशोधन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या उद्देश्य है, अर्थात्, दूर-दराज के स्थानों ठीक होना रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतों को दूर करना ताकि उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सके।इस प्रकार, संशोधित प्रावधान मजिस्ट्रेट पर आदेशिका जारी करने से पहले जांच या प्रत्यक्ष जांच करने का दायित्व डालता है, ताकि झूठी शिकायतों को फ़िल्टर और खारिज किया जा सके।उक्त संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक के साथ संलग्न ध्यान दें में उपरोक्त उद्देश्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।"

22. लोकेश कुमार जैन (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित होना आपराधिक मामलों के संबंध में विभागीय कार्यवाही के दायरे पर चर्चा की।पैरा 23 और 24 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "23. **P.S** में। राज्य बनाम बिहार राज्य *[(1996) 9* एससीसी 1:1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 897], इस न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता को केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आलोक में विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।आपराधिक मामला लंबे समय से लंबित होना था, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता को उसी आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था।
>
> **24.** उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि विभागीय कार्यवाहियों में समान आरोप स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, तो कोई आश्चर्य करता है कि आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए क्या है जहां अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक विभागीय कार्यवाहियों में अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक से कहीं अधिक है।"

23. पी. चिदम्बरम (उपर्युक्त) के खंड में, दुर्भावपूर्ण उच्चतम न्यायालय ने अन्य दुरुपयोग के निहित निहित निहित-निहित यह भी कहा कि "..जाँच आदेशिका की निगरानी करना न्यायालय का कार्य नहीं है जब तक कि जाँच कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।जाँच की प्रक्रिया तय करना जाँच एजेंसी के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए...।.."

24. विनय त्यागी (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे की जांच और नए सिरे से जांच के बीच के अंतर पर चर्चा की।

> "22. "आगे की जाँच" वह जगह है जहाँ जाँच अधिकारी खंड 173 (8) के संदर्भ में अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद आगे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है।यह शक्ति कार्यपालिका के पास निहित है।यह पिछली जाँच की निरंतरता है और इसलिए, इसे "आगे की जाँच" के रूप में समझा और वर्णित किया जाता है।इस तरह की जांच का दायरा आगे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की खोज तक ही सीमित है।इसका उद्देश्य अदालत के समक्ष सही तथ्यों को लाना है, भले ही वे प्राथमिक जांच के लिए बाद के चरण में पाए जाएं।इसे आमतौर पर "पूरक रिपोर्ट" के रूप में वर्णित किया जाता है।"पूरक रिपोर्ट" सही अभिव्यक्ति होगी क्योंकि बाद की जांच का उद्देश्य अधिकार प्राप्त पुलिस अधिकारी द्वारा की गई प्राथमिक जांच को पूरा करना है।आगे की जाँच की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका जाँच एजेंसी द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने का प्रभाव नहीं पड़ता है।यह पिछली जांच की एक तरह की निरंतरता है।इसका आधार नए साक्ष्य की खोज और उसी अपराध की निरंतरता और उसी घटना से संबंधित घटनाओं की श्रृंखला है।दूसरे शब्दों में, इसे "पुनर्निरीक्षण", "ताजा" या "डी नोवो" जांच के पूर्ण विरोधाभास में समझना होगा।
>
> **23.** हालाँकि, "नई जाँच", "नई जाँच" या "नई जाँच" के मामले में अदालत का एक निश्चित आदेश होना चाहिए।न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या पिछली जांच, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कार्रवाई करने में असमर्थ है।न तो जांच एजेंसी और न ही मजिस्ट्रेट के पास "नई जांच" का आदेश देने या संचालन करने की कोई शक्ति है।यह मुख्य रूप से इस कारण से है कि यह संहिता की योजना का विरोध करेगा।यह आवश्यक है कि उच्च न्यायपालिका द्वारा पारित "नए सिरे से"/"नए सिरे से" जांच के आदेश को भी हमेशा पहले से की गई जांच के भाग्य के बारे में एक विशिष्ट निर्देश के साथ जोड़ा जाना चाहिए।जिन मामलों में इस तरह का निर्देश जारी किया जा सकता है, वे बहुत कम हैं।यह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मौलिक सिद्धांत पर आधारित है जो यह है कि एक संदिग्ध या आरोपी का न्यायसंगत और निष्पक्ष जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार है।यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में निहित संवैधानिक जनादेश से निकलता है।जहां जांच अनुचित, दागी, दुर्भावपूर्ण और गलत तरीके से की जाती है, अदालतें इस तरह की जांच को रद्द देंगी और नए सिरे से या नए सिरे से जांच का निर्देश देंगी और यदि आवश्यक हो, तो किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा भी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह व्यापक प्रचुरता की एक शक्ति है और इसलिए, इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत ऐसे मामलों पर पूरी तरह से लागू होगा।जब तक जांच की अनुचितता ऐसी नहीं है कि यह अदालत की न्यायिक अंतरात्मा को आहत करती है, तब तक अदालत को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए ताकि जांच को रद्द किया जा सके और "नए सिरे से जांच" का निर्देश दिया जा सके।

<u>राज्य की ओर से</u>

25. विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करेंगे कि तत्काल मामले में, आई. ओ. ने संहिता की खंड 161 या 164 के तहत सभी पीड़ितों का बयान दर्ज नहीं किया; जांच दोषपूर्ण है।राज्य के विद्वान वकील भी

निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में मानने के बाद, संहिता की धारा 200 और 202 के तहत जांच किए बिना, याचिकाकर्ता को तलब नहीं किया जा सकता था।इसलिए, 15.11.2019 दिनांकित समन आदेश कानून की नजर में बुरा है।राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यदि 15.11.2019 दिनांकित समन आदेश को अभिखंडित कर दिया जाता है तो न्यायालय आगे की जांच का आदेश दे सकता है।

<u>डीडी की ओर से</u>

26. डीडी की ओर से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि तत्काल मामले में जांच काफी दोषपूर्ण है।उन्होंने अपने तर्कों में निम्नलिखित बिंदु उठाए:-

(i) तत्काल मामले में, पहली रिपोर्ट स्कूल के पी. टी. ए. द्वारा दर्ज की गई थी।एफ. आर. पर विचार के समय पी. टी. ए. को सूचित नहीं किया गया था।

(ii) रिपोर्ट के अनुसार कई पीड़ित भी थे, लेकिन उन सभी से संहिता की खंड 161 या संहिता की खंड 164 के तहत पूछताछ नहीं की गई थी।

(iii) डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने कोई विरोध याचिका दायर नहीं की।विरोध याचिका पर विचार करते समय उनका बयान दर्ज किया गया था।अपने बयान के पैरा 16,17 और 18 में उन्होंने इस मामले का समर्थन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा छात्रों का यौन उत्पीड़न किया गया था।

(iv) डीडी पीड़ित है।उन्हें विरोध याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है।

(v) संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज किया गया बयान प्राप्त किया गया प्रतीत होता है।वे सभी साइक्लोस्टाइल वाले कथन हैं।

(vi) डीडी द्वारा दायर विरोध याचिका पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग नहीं लगाया।

(vii) एफ. आर. के विचार के समय दर्ज सूचना देने वाले का बयान कानून के अनुसार नहीं है।इसे नहीं पढ़ना चाहिए।

(viii) एफ. आर. को सूचना देने वाले के बयान पर विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए एफ. आर. दिनांक <आई. डी. 1> को स्वीकार करने वाले आदेश को रद्द दिया जाना चाहिए।

(ix) वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि यदि उत्तम सिंह नेगी के बयान को विरोध याचिका माना जाता है, तो इसके पैरा 16,17 और 18 याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को साबित करते हैं।

(x) एफ. आर. इस आधार पर दायर नहीं किया गया था कि कोई अपराध नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एफ. आर. में दर्ज किया गया है कि सबूत एकत्र नहीं किया जा सका है।

(xi) मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को शिकायत मानते हुए सीधे आरोपी को तलब कर सकता है और उसे संहिता की धारा 200 और 202 के तहत जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यह आगे की जांच के लिए उपयुक्त मामला है।उनके दलील के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने गंगाधर जनार्दन म्हात्रे (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर भरोसा रखा है।पैरा 9 में इसके निचले भाग का उल्लेख किया गया है, जो नीचे दिया गया है:-

> "9. मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की अनदेखी कर सकता है और स्वतंत्र रूप से जांच से सामने आने वाले तथ्यों पर अपना दिमाग लगा सकता है और मामले का संज्ञान ले सकता है, यदि वह उचित समझता है, तो खंड 190 (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आरोपी को आदेशिका जारी करने का निर्देश दे सकता है।मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में खंड 190 (1) (ए) के तहत किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए संहिता की खंड *200* और 202 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि वह खंड 200 या खंड *202* के तहत भी कार्य कर सकता है।[इंडिया कैरेट (पी) लिमिटेड बनाम देखें।कर्नाटक राज्य [(1989) 2 एस. सी. सी 132:1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 307:ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 885]जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने और मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो सूचना देने वाला पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जहां मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है और कार्यवाही को छोड़ देता है या यह विचार रखता है कि कुछ के खिलाफ कार्यवाही के लिए सामग्री है और दूसरों के संबंध में अपर्याप्त आधार हैं, तो सूचना देने वाला निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा क्योंकि दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पूरी तरह या आंशिक रूप से अप्रभावी हो जाती है।इसलिए, इस न्यायालय ने भगवंत सिंह मामले [(1985) 2 एस. सी. सी. 537 में संकेत दिया:1985 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 267:ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1285] कि जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को छोड़ने का निर्णय लेता है या यह विचार रखता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, सूचना देने वाले को नोटिस देना और मामले में सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य हो जाता है।जैसा कि ऊपर बताया गया है, संहिता में इस संबंध में नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।"

चर्चा

28. तत्काल मामले में तथ्य विवाद में नहीं हैं।इन्हें संक्षेप में कालक्रम में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः-

(i) स्कूल के पी. टी. ए. ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता द्वारा यौन आक्रमण और आक्रमण की रिपोर्ट दी।यह रिपोर्ट एसएसपी, उधम सिंह नगर, शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासन को भी दी गई थी।

(ii) एसएसपी, उधम सिंह नगर ने अपने दिनांकित 19.05.2014 और 23.05.2014 पत्र के माध्यम से सर्कल अधिकारी, सितारगंज, उधम सिंह नगर को इसकी जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

(iii) डॉ. उत्तम सिंह नेगी, सर्कल अधिकारी सितारगंज, उधम सिंह नगर ने जांच की और दिनांक 26.07.2014 पर रिपोर्ट दायर की।

(iv) एस. एस. पी. के आदेश के तहत, यह रिपोर्ट दिनांक <आई. डी. 1> को प्राथमिकी आर. नं. 2015 का 53.

(v) प्राथमिकी आर. नं. 2015 का 53, जाँच के बाद, एफ. आर. प्रस्तुत किया गया था।

(vi) एफ. आर. के समय अदालत ने सूचना देने वाले डॉ. उत्तम सिंह नेगी को नोटिस जारी किया।उनका बयान पहले विविध मामले में 10.12.2018 पर दर्ज किया गया था और उसके बाद, FR को 14.01.2019 पर स्वीकार कर लिया गया था।

(vii) डीडी ने विविध मामले में 14.10.2019 दिनांकित विरोध याचिका दायर की जिसमें मांग की गई कि 14.01.2019 दिनांकित आदेश को रद्द किया जाए, संज्ञान लिया जाए और याचिकाकर्ता को तलब किया जाए।

(viii) 15.11.2019 पर अदालत ने 14.01.2019 के पहले के आदेश को रद्द नहीं किया, लेकिन विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में माना और याचिकाकर्ता को सीधे भा.दं.सं. सी. की खंड 377,506, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की खंड 67 और पॉक्सो अधिनियम की खंड 5/6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तलब किया।

अंतिम रिपोर्ट और उसका विवरण

29. यह अच्छी तरह से तय है कि मजिस्ट्रेट आई. ओ. द्वारा बनाई गई राय से बाध्य नहीं है। मामले में अभिनंदन झा और अन्य बनाम दिनेश मिश्रा [11]. माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि खंड 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी कि किसी आरोपी को मुकदमे के लिए बुलाने का कोई मामला नहीं बनता है, एक मजिस्ट्रेट आगे का आदेश दे सकता है।

[11] (1967) 3 एस. सी. सी. 668

संहिता की खंड 156 (3) के तहत जांच।यदि विरोध याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो उन्हें शिकायत के रूप में माना जा सकता है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

30. H.S के मामले में। बैन्स (ऊपर), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कानून निर्धारित किया।H.S के मामले में। बैन्स (ऊपर), वास्तव में, मजिस्ट्रेट के पास एक शिकायत की गई थी।जिस मजिस्ट्रेट को शिकायत की गई थी, उन्होंने संहिता की खंड 156 (3) के तहत जांच का आदेश दिया।पुलिस ने जांच के बाद एफ. आर. प्रस्तुत किया। इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार**,** एक मजिस्ट्रेट**,** जो शिकायत प्राप्त होने पर**,** खंड **156 (3)** के तहत जांच का आदेश देता है और खंड **173 (1)** के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करता है**,** उसके बाद**,** तीन चीजों में से एक कर सकता है:**(1)** वह यह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने और कार्रवाई छोड़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है**;**

(2) **वह पुलिस रिपोर्ट और जारी करने की प्रक्रिया के आधार पर खंड 190 (1) (बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है; यह वह पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में आए निष्कर्ष से किसी भी तरह से बाध्य हुए बिना कर सकता है; (3) वह मूल शिकायत के आधार पर खंड 190 (1) (ए) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और खंड 200 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से शपथ लेकर पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ सकता है।**(जोर दिया गया)

31. यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि H.S के मामले में। बैन्स (ऊपर), शुरू में, मजिस्ट्रेट को एक शिकायत दी गई थी, जिस पर संहिता की खंड 156 (3) के तहत जांच का आदेश दिया गया था।दूसरे शब्दों में, H.S के मामले में। बैंस (ऊपर), संहिता की खंड 154 के तहत पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी, मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी; प्राथमिकी का आधार एक शिकायत थी।

32. भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में, जैसा कि कहा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतिम रिपोर्ट पर विचार करते समय, सूचना देने वाले को नोटिस दिया जाना चाहिए; मजिस्ट्रेट पीड़ित या उसके रिश्तेदारों को नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वे उपस्थित होते हैं तो उन्हें सुना जा सकता है।

33. राकेश और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरे के मामले में [12]. एच. एस. बैन्स (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों को दोहराया गया है।

34. जैसा कि एफ. आर. की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट अभिनंदन झा (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे की जांच आवश्यक है, तो वह संहिता की खंड 156 (3) के तहत उस आशय का आदेश दे सकता है।

35. विष्णु कुमार तिवारी (ऊपर) के मामले में, कानून के सिद्धांत, जैसा कि अभिनंदन झा (ऊपर) और H.S के मामलों में निर्धारित किए गए हैं। बैन्स (उपरोक्त) मामले पर भी विचार किया गया है।स्थिर स्थिति इस प्रकार निकलती है:-

> "यदि जाँच के बाद, आई. ओ. एक रिपोर्ट दाखिल करता है जो दर्शाता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के पास निम्नलिखित विकल्प हैं:-
>
> (1) मजिस्ट्रेट आई. ओ. की राय से सहमत हो सकता है और एफ. आर. प्रतिग्रहण करना कर सकता है और कार्यवाही को बंद कर सकता है।
>
> (2) मजिस्ट्रेट आई. ओ. की राय से भिन्न हो सकता है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से बने अपराध के लिए सीधे आरोपी को तलब कर सकता है।यह संहिता की खंड 190 (1) (बी) के तहत किया जा सकता है।
>
> (3) मजिस्ट्रेट आगे की जाँच का आदेश दे सकता है, यदि उसे पता चलता है कि जाँच कानून के अनुसार नहीं की गई थी।
>
> (4) किसी भी मामले में, एफ. आर. पर विचार करने से पहले, मजिस्ट्रेट सूचना देने वाले नोटिस जारी करना करेगा।यदि सूचना देने वाला विरोध याचिका दायर करता है, तो मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मान सकते हैं और संहिता के अध्याय XV के तहत आगे बढ़ सकते हैं।यदि शिकायत की आवश्यकता है तो विरोध याचिका को शिकायत के रूप में माना जा सकता है।

प्राथमिकी आर. बनाम शिकायत बनाम विरोध याचिका

36. जैसे-जैसे कोई एफ. आर. प्रस्तुत किया जाता है, ये वाक्यांश सामने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अंतिम रिपोर्ट को भी संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है।यह जांच के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि नहीं

[12] (2014) 13 एससीसी 133

अपराध किया जाता है।जहाँ तक "शिकायत" का संबंध है, इसे संहिता की खंड 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो कि नीचे दिया गया है:-

> "2 (घ)" "शिकायत" "से किसी मजिस्ट्रेट पर इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई आरोप अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, ने अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।"
>
> स्पष्टीकरण।- किसी मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई एक रिपोर्ट जो जांच के बाद, एक गैर-हस्तक्षेप अपराध के होने का खुलासा करती है, उसे शिकायत माना जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट दी जाती है, उसे शिकायतकर्ता माना जाएगा:"

37. परिभाषा के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि एक शिकायत मौखिक हो सकती है और शिकायत के लिए कोई प्रारूप नहीं है।शिकायत का सार यह है कि अपराध करने वाले किसी भी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संहिता के तहत कार्रवाई करने के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट पर आरोप लगाए जाते हैं।यह पुलिस रिपोर्ट नहीं है।

38. "प्रथम सूचना रिपोर्ट" शब्द भी संहिता के तहत परिभाषित नहीं हैं।लेकिन, यह हस्तक्षेप अपराध के बारे में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई रिपोर्ट को संदर्भित करता है। यह जानकारी संहिता की खंड 154 के तहत दी गई है।

39. शिकायत और एफ. आई. आर. के बीच व्यापक अंतर किया जा सकता है। एक ओर, मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करना आवश्यक है, जबकि मजिस्ट्रेट के पास प्राथमिकी नहीं की जाती है।संहिता की खंड 154 के तहत हस्तक्षेप अपराध की जानकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है जिसे प्राथमिकी आर. के रूप में जाना जाता है। प्राथमिकी आर. का भी कोई प्रारूप नहीं है।इस पहलू पर कानून काफी विस्तार से है कि एक प्राथमिकी आर. क्या है। कानून यह तय करता है कि प्राथमिकी आर. बहुत गुप्त नहीं होनी चाहिए।साथ ही, इसे प्रत्येक तथ्य का विश्वकोश नहीं माना जा सकता है, जो अपराध का गठन करता है।वास्तव में, प्राथमिकी आर. का उद्देश्य पुलिस को हस्तक्षेप अपराध की जानकारी देकर न्यायाधीश के चक्र को गति देना है।

40. "विरोध याचिका" को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है।इसे संहिता में कहीं भी संदर्भित नहीं किया गया है।यह प्रथा है, जिसने विरोध याचिका को मान्यता दी है।यहां तक कि अभिनंदन झा (उपरोक्त) के मामले में भी विरोध याचिका दायर की गई थी।वास्तव में, इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है।

एफ. आर. इसमें कई प्रार्थनाएँ या कोई भी प्रार्थना हो सकती है जिसमें-(i) एफ. आर. को अस्वीकार करना और संहिता की खंड 190 (1) (बी) के तहत आरोपी को तलब करना, या आगे की जांच के लिए आदेश देना या विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मानना शामिल है।ये केवल चित्र हैं।

41. याचिकाकर्ता की ओर से, विष्णु कुमार तिवारी (उपरोक्त) के मामले में फैसले का संदर्भ दिया गया है, यह तर्क देने के लिए कि प्रत्येक विरोध याचिका को शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है।विरोध याचिका को केवल शिकायत के रूप में माना जा सकता है जब यह शिकायत की आवश्यकता को पूरा करती है।विष्णु कुमार तिवारी (ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 46 में कहा कि "यदि कोई विरोध याचिका शिकायत की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मान सकते हैं और संहिता की खंड **202** के साथ पठित खंड **200** के तहत उसी के साथ व्यवहार कर सकते हैं।इस मामले में, वास्तव में, विरोध याचिका में गवाहों की कोई सूची नहीं है।विरोध याचिका में प्रार्थना अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने और अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ आवेदन की अनुमति देने की है।हालांकि हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि प्रपत्र पूरी तरह से इस प्रश्न का निर्णायक होना चाहिए कि क्या यह एक शिकायत के बराबर है या एक शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए, हम सोचेंगे कि अनिवार्य रूप से, इस मामले में विरोध याचिका, अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ दूसरे प्रतिवादी की आपत्तियों का सारांश है।"

42. विभिन्न मामलों में रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद विरोध याचिका दायर करने पर विचार किया गया है।विष्णु कुमार तिवारी (ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-

> "21. प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने वाले मुखबिर द्वारा विरोध याचिका दायर करने के संबंध में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है:(गंगाधर जनार्दन म्हात्रे मामला [गंगाधर जनार्दन म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) *7* एस. सी. सी. *768:2005* एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 404], एस. सी. सी. पीपी. 772-74, पैरा 6 &
> 9)
>
> > "6. संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने वाले मुखबिर द्वारा विरोध याचिका दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।लेकिन यह प्रथा रही है।विरोध याचिका दायर करने से संबंधित संहिता में प्रावधान की अभाव पर विचार किया गया है।यह न्यायालय

भगवंत सिंह बनाम कम्र में।पुलिस का [भगवंत सिंह बनाम कमांडर।पुलिस विभाग, *(1985) 2* एस. सी. सी. 537:1985 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 267] ने खंड 173 (2) के तहत बनाई गई रिपोर्ट के विचाराधीन होने पर सूचना देने वाले को सूचना देने की वांछनीयता पर जोर दिया।न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:(एस. सी. सी. पी. 542, पैरा 4)

'4.... इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब खंड 173 की उप-खंड (2) (i) के तहत किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करने पर, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो सूचना देने वाले को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने के लिए राजी करने के लिए अपनी दलीलें दे सके।तदनुसार हमारा विचार है कि जिस मामले में मजिस्ट्रेट को खंड *173* की उप-खंड *(2) (i)* के तहत एक रिपोर्ट भेजी जाती है, वह अपराध का संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को छोड़ने का फैसला करता है या यह विचार रखता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देना चाहिए और रिपोर्ट पर विचार करने के समय उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।'

23. किशोर कुमार ज्ञानचंदानी बनाम *G.D.* मेहरोत्रा [किशोर कुमार ज्ञानचंदानी बनाम *G.D.* मेहरोत्रा, (2011) 15 SCC 513:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 633], कुछ अपराधों के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जिसे स्वीकार कर लिया गया।लगभग तीन महीने बाद, एक विरोध याचिका दायर की गई।मजिस्ट्रेट ने इसे एक शिकायत के रूप में मानने का निर्देश दिया।उन्होंने संहिता की खंड 202 के तहत जांच की और संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़े।पैरा 4 प्रासंगिक है और यह इस प्रकार है:(एस. सी. सी. पी. 514, पैरा 4)

"4. पक्षों के बीच कुछ विवाद है कि मजिस्ट्रेट द्वारा 27-1 पर अंतिम प्रपत्र स्वीकार करने से पहले शिकायतकर्ता को नोटिस दिया गया था और शिकायतकर्ता ने आपत्ति दर्ज नहीं की थी, जबकि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसे अदालत से कोई नोटिस नहीं मिला था।जो भी हो, हम मौजूदा मामले का निर्णय लेने के लिए उस विवाद में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे विचार में फिर भी से भौतिक नहीं है और न ही यह अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र को हटा देता है, भले ही उसने पहले ही अंतिम प्रपत्र स्वीकार कर लिया हो, जो पुलिस द्वारा दायर किया गया हो।"

24. वास्तव में, इस मामले का निर्णय स्वयं इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा न्यायालय में राय के विचलन को देखते हुए किया गया था। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:(किशोर कुमार ज्ञानचंदानी मामला [किशोर कुमार ज्ञानचंदानी बनाम *G.D.* मेहरोत्रा, *(2011)* 15 *SCC 513:(2012)* 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 633], एस. सी. सी. पी.514, पैरा 6)

"6. यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब पुलिस जांच के बाद संहिता की खंड 173 के तहत अंतिम फॉर्म दाखिल करती है, तो मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष से असहमत हो सकते हैं।

पुलिस पहुंची और संहिता की खंड 190 के तहत शक्ति के प्रयोग में संज्ञान लिया ।मजिस्ट्रेट संहिता की खंड 156 के तहत मामले में संज्ञान नहीं ले सकते हैं और आगे की जांच का निर्देश नहीं दे सकते हैं ।जहाँ मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रपत्र को स्वीकार करता है, शिकायतकर्ता का नियमित शिकायत दर्ज करने का अधिकार छीन नहीं लिया जाता है और वास्तव में ऐसी शिकायत दर्ज होने पर मजिस्ट्रेट संहिता की खंड 201 के तहत प्रक्रिया का पालन करता है और यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री अपराध साबित होती है तो संज्ञान लेता है ।इस प्रश्न को इस न्यायालय द्वारा गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा [गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा, (1982) *3* एस. सी. सी. *510* में उठाया और सिद्ध गया है ।
:1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 110] जिसके तहत दृष्टिकोण [भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य, 1980 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 165:इसके विपरीत पटना उच्च न्यायालय के 1981 सी. आर. आई. एल. जे. 795] को उलट दिया गया है। न्यायालय ने उपरोक्त मामले में अनिश्चित शब्दों में संकेत दिया है कि अंतिम प्रपत्र की स्वीकृति मजिस्ट्रेट को शिकायत कार्यवाही में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर संज्ञान लेने से नहीं रोकती है ।"

(जोर दिया गया)

43. राकेश (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोपाल विजय वर्मा बनाम भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा के मामले में निर्णय का उल्लेख किया। [13.] , जिसमें यह कहा गया था कि "उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से यह सोचने में गलती कर रहा था कि मजिस्ट्रेट शिकायत पर किसी मामले का संज्ञान नहीं ले सकता था क्योंकि उसने पहले पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था ।उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द दिया जाता है ।मामला कानून के अनुसार निपटारे के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पटना को भेजा जाता है ।यदि अभियुक्तों को कोई और आपत्ति उठानी है, तो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कर सकते हैं।"

44. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह नीचे स्पष्ट है:-

(i) "एफ. आई. आर". को संहिता की खंड 2 (डी) के तहत परिभाषित "शिकायत" नहीं कहा जा सकता है।

(ii) "शिकायत" को संहिता की खंड 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो एक मजिस्ट्रेट को दी जाती है।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई हस्तक्षेप अपराध की रिपोर्ट होती है।

[13] (1982) 3 एससीसी 510

(iv) मजिस्ट्रेट अपने समक्ष की गई शिकायत पर जाँच का आदेश दे सकता है। ऐसे मामलों में, अदालत के पास जानकारी, मूल शिकायत के साथ-साथ प्राथमिकी आर. दोनों होती हैं। दोनों एक ही हैं।H.S के मामले में। (ऊपर), यह एक ऐसी स्थिति थी जब न्यायालय ने कहा कि वास्तव में, यदि एफ. आर. दायर किया जाता है, तो न्यायालय मूल शिकायत पर संज्ञान ले सकता है।

(v) यदि पुलिस जाँच के बाद एफ. आर. दर्ज करती है और मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसी अपराध के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है।यह वर्जित नहीं है।यदि ऐसी शिकायत दर्ज की जाती है, तो यह संहिता के अध्याय XV के तहत आगे बढ़ेगी।

दूसरी शिकायत पर सहमति

45. तत्काल मामले में, 15.11.2019 पर, डीडी द्वारा दायर विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में मानते हुए संज्ञान लिया गया था।समन आदेश को चुनौती देने के लिए मुख्य रूप से तीन बहस हैं, अर्थात्, (i) विरोध याचिका में शिकायत की सभी आवश्यकताएं होनी चाहिए, इससे पहले कि इसे शिकायत के रूप में माना जाए और (ii) शिकायत पर समन करने से पहले संहिता की धारा 200 और 202 के तहत जांच अनिवार्य है; (iii) समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें असाधारण स्थिति न हो जैसा कि प्रमथ नाथ तालुका (ऊपर) के मामले में निर्धारित किया गया है, जैसा कि महेश चंद *(ऊपर)* के मामले में संदर्भित है।

46. न्यायालय सबसे पहले यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या डीडी द्वारा दायर विरोध याचिका को शिकायत के रूप में माना जा सकता है।

47. जैसा कि यहाँ पहले चर्चा की गई है, ऐसा कोई प्रारूप नहीं है जिसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत की जा सके।डीडी द्वारा दायर विरोध याचिका रिकॉर्ड में है।यह काफी विस्तार से बताया गया है।यह विवरण देता है कि याचिकाकर्ता द्वारा डीडी और अन्य पीड़ितों के साथ अपराध कैसे किया गया था; जब याचिकाकर्ता द्वारा डीडी का यौन आक्रमण किया गया था और यह कैसे किया गया था। घटनाओं का विवरण देने के बाद (वास्तव में, यह काफी विस्तार से है), डीडी ने अनुरोध किया कि <आईडी1> दिनांकित पूर्व आदेश, जिसके द्वारा एफआर स्वीकार किया गया था, को रद्द कर दिया जाए और संज्ञान लिया जाए और याचिकाकर्ता को तलब किया जाए।विरोध याचिका संहिता की खंड 2 (डी) के सभी घटकों को शिकायत के रूप में माने जाने के योग्य बनाती है।

48. तर्क के समय, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि विरोध याचिका में गवाहों की कोई सूची नहीं थी, जैसा कि संहिता की खंड 204 (2) के तहत दायर करने की आवश्यकता थी।यह न्यायालय इस पर आगे चर्चा करने का इरादा नहीं रखता है।यह सच है कि विष्णु (ऊपर) के मामले में, पैरा 46 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गवाहों की सूची का उल्लेख किया, जो उस मामले में विरोध याचिका के साथ संलग्न नहीं था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने विष्णु कुमार तिवारी (ऊपर) के मामले में कोई कानून नहीं बनाया कि यदि गवाहों की सूची विरोध याचिका के साथ संलग्न नहीं है, तो इसे शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है।शिकायत पर संज्ञान कैसे लिया जाता है, इसकी तुलना में शिकायत क्या है, यह काफी अलग है।जैसा कि कहा गया है, शिकायत को संहिता की खंड 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है और डीडी द्वारा दायर तत्काल मामले में विरोध याचिका को निश्चित रूप से संहिता की खंड 2 (डी) के अनुसार शिकायत के रूप में माना जा सकता है।अब सवाल यह है कि अगर डीडी द्वारा विरोध याचिका के साथ गवाहों की सूची दायर नहीं की जाती है, तो क्या यह विरोध याचिका को शिकायत के रूप में माने जाने के लिए अयोग्य बनाता है। जवाब निश्चित रूप से नकारात्मक है, क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी होने से पहले संहिता की खंड 204 (2) के तहत गवाहों की सूची दायर करने की आवश्यकता थी।इसलिए, केवल इसलिए कि विरोध याचिका के साथ गवाहों की सूची दायर नहीं की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि विरोध याचिका को शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है।डीडी द्वारा दायर तत्काल मामले में विरोध याचिका को शिकायत के रूप में माना जा सकता है और इसे माना जा सकता है ताकि कानून की कोई त्रुटि न हो।

<u>दूसरी शिकायत</u>

49. अगला सवाल यह है कि क्या विरोध याचिका दूसरी शिकायत है?परमानंद तालुकदार (ऊपर) और महेश चंद (ऊपर) के मामलों में याचिकाकर्ता की ओर से संदर्भ दिया गया है।कानून निर्वात में काम नहीं करता है।यह आत्यन्तिक रूप से नहीं हो सकता है।परमानंद तालुकदार (ऊपर) के मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू में एक शिकायत को खारिज कर दिया गया था।इसके संशोधन को भी खारिज कर दिया गया था।माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपील के लिए विशेष अनुमति को बाद में वापस ले लिया गया।फिर उस आदेश के 22 दिनों के भीतर एक नई शिकायत दर्ज की गई और दूसरी शिकायत पर संज्ञान लिया गया।मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि पहली शिकायत को खारिज नहीं किया गया था।

कानून की बात है, दूसरी शिकायत के मनोरंजन के लिए बाधा के रूप में कार्य करें। यह उन तथ्यों के तहत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है। जहां पिछला आदेश अपूर्ण अभिलेख या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से हास्यास्पद तर्क, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ पिछली कार्यवाही में अभिलेख पर नहीं लाए जा सकते थे, प्रस्तुत किया गए हैं।

50. महेश चंद (उपरोक्त) के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के दौरान एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई।जाँच के बाद, आई. ओ. ने एफ. आर. प्रस्तुत किया। मुखबिर ने विरोध याचिका दायर की।इसके बाद एफआर को स्वीकार कर लिया गया और शिकायत को भी बंद कर दिया गया।इसके बाद तीसरी शिकायत दर्ज की गई, जिस पर संज्ञान लिया गया।इस मामले की सुनवाई करते हुए, माननीय न्यायालय ने समान तथ्यों पर बाद की शिकायत की स्वीकार्यता के संबंध में प्रमथ नाथ तालुकदार (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों को मंजूरी दी।

51. तत्काल मामले में, वास्तव में, स्कूल के पी. टी. ए. द्वारा कथित रूप से दी गई रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है।उस रिपोर्ट पर, सूचना देने वाले द्वारा एक जांच की गई थी, जो सर्कल अधिकारी, पुलिस था और यह वह रिपोर्ट है जिसे प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें जांच के बाद, एफआर प्रस्तुत किया गया था।वास्तव में इस मामले में कोई शिकायत नहीं है।शुरू में, पी. टी. ए. ने मजिस्ट्रेट के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।उन्होंने कथित तौर पर पुलिस प्रशासन और स्कूल के अधिकारियों को अपराध की जानकारी दी, न कि मजिस्ट्रेट को।उस रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई। जाँच रिपोर्ट को भी शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसे एसएसपी, उधम सिंह नगर को प्रस्तुत किया गया था।इसलिए, तत्काल मामले में एफ. आर. दायर करने से पहले अतीत में कोई शिकायत नहीं हुई है।14.01.2019 पर, जब FR पर विचार किया गया था, तो अदालत के समक्ष कोई विरोध याचिका नहीं थी।सूचना देने वाले का बयान दर्ज किया गया था, लेकिन इस तरह का बयान दर्ज करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है।पहले विविध मामले में दर्ज डॉ. उत्तम सिंह नेगी के उस बयान को किसी भी तरह से विरोध याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता है।

52. समता नायडू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में[14] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थिति पर चर्चा की जब दूसरी विरोध याचिका दायर की गई थी और जैसा कि नीचे कहा गया है:

> "15. हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने शिवशंकर सिंह [शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 1 एस. सी. सी. 130: मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैरा *18* पर रिलायंस को रखा था।(2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 513]उस मामले में, पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने से पहले ही शिकायतकर्ता द्वारा विरोध याचिका दायर की गई थी।जबकि उक्त विरोध याचिका लंबित होना थी, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसके बाद दूसरी विरोध याचिका दायर की गई थी।अभियुक्त द्वारा उठाई गई चुनौती कि दूसरी विरोध याचिका अनुरक्षणीय नहीं थी, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई थी [आनंद कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, *2009* एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 857:(2010) 1 पीएलजेआर 167]।इन तथ्यों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर निम्नानुसार विचार किया गया:(शिवशंकर सिंह मामला [शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 1 एस. सी. सी. *130:(2012)* 1 एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*)* 513] एससीसी पीपी। 133-34 & 136, पैरा 7 & 18-19)
>
>> "7. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने कहा है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले दायर की गई तथाकथित पहली विरोध याचिका अनुरक्षणीय नहीं थी और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।विद्वत मजिस्ट्रेट ने उक्त विरोध याचिका के आधार पर आगे नहीं बढ़े और यह फाइल में केवल एक दस्तावेज बना रहा।दूसरी याचिका एकमात्र विरोध याचिका थी जिस पर विचार किया जा सकता था क्योंकि यह अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद दायर की गई थी।...
>>
>> *18.* इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पहले की शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या आदेश पारित किया गया हो, शिकायत की प्रकृति को समझे बिना या पूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सका हो या जहां शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद कुछ तथ्यों का पता चला हो, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक सकता था।हालाँकि, दूसरी शिकायत बनाए अनुरक्षणीय नहीं होगी जिसमें शिकायतकर्ता के मामले पर योग्यता के आधार पर पूर्ण विचार करने पर पहले की शिकायत का निपटारा कर दिया गया है।
>>
>> *19.* विरोध याचिका को हमेशा एक शिकायत के रूप में माना जा सकता है और सीआरपीसी के अध्याय XV के संदर्भ में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यदि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर विचार करने के लिए कोई रोक नहीं है, तो असाधारण परिस्थितियों में, दूसरी विरोध याचिका पर भी इसी तरह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है।यदि पहली विरोध याचिका मामले का फैसला करने के लिए आवश्यक पूर्ण तथ्यों/विवरणों को प्रस्तुत किए बिना दायर की गई है, और अदालत द्वारा इसके मनोरंजन से पहले, पूर्ण विवरण देते हुए एक नई विरोध याचिका दायर की जाती है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इसे बनाए अनुरक्षणीय क्यों नहीं होना चाहिए।"" ""
>
> (जोर दिया गया)

53. जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एफ. आर. दाखिल करने से पहले तत्काल मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।किसी भी शिकायत का कभी फैसला नहीं किया गया।द.

---

[14] (2020) 5 एस. सी. सी. 378

प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच की गई और एफ. आर. प्रस्तुत की गई। 14.01.2019 पर एफ. आर. पर विचार करते समय, न्यायालय के समक्ष कोई विरोध याचिका नहीं थी।आई. डी. 1 दिनांकित विरोध याचिका, वास्तव में, तत्काल मामले में पहली विरोध याचिका थी।इस विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में माने जाने की सभी आवश्यकताएं थीं और इसे सही तरीके से माना गया था।इसलिए, यह अदालत निष्कर्ष निकालती है कि नीचे दिए गए न्यायालय ने डीडी द्वारा दायर <आईडी1> की विरोध याचिका को शिकायत के रूप में मानने में कोई त्रुटि नहीं की।पहली शिकायत पर संज्ञान लिया गया था। यह दूसरी शिकायत नहीं थी।क्या संज्ञान कानून के अनुसार था, यह एक अलग मुद्दा है, जिससे अब निपटा जाएगा।

<u>संहिता की धारा 200 और 202 के तहत जांच</u>

54. तत्काल मामले में, 14.01.2019 पर FR स्वीकार किया गया था।इसके बाद, 14.10.2019 पर विरोध याचिका दायर की गई, जिसे 15.11.2019 पर शिकायत के रूप में माना गया और तुरंत संज्ञान लिया गया।शिकायत से निपटने की प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के तहत दी गई है।संहिता की खंड 200 इस प्रकार है:-

> "200। शिकायतकर्ता की जाँच।- शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और मौजूदा गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ लेकर जांच करेगा और ऐसी जांच के सार को लिखित कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता और गवाहों और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे:
>
> बशर्ते कि, जब शिकायत लिखित रूप में की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है -
>
> (a) यदि कोई लोक सेवक जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के बर्खास्तगी में कार्य कर रहा है या कार्य करने का इरादा रखता है या अदालत ने शिकायत की है; या
>
> (b) यदि मजिस्ट्रेट खंड 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जांच या मुकदमे के लिए मामला सौंपता है:
>
> बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने के बाद खंड 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला सौंपता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनसे फिर से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।"

55. खंड 200 के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत की जांच की जाएगी।परंतुक लोक सेवक या अन्य मामलों के मामले में अपवाद देता है।

56. संहिता की खंड 202 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करने के बजाय या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या मामले की जांच करने का निर्देश दे सकता है।

जांच पड़ताल की ।लेकिन सभी मामलों में, जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, वह हमेशा संहिता की खंड 202 के तहत जांच करेगा या उस खंड के तहत जांच के लिए आदेश देगा ।इसे टाला नहीं जा सकता ।तत्काल मामले में, हालांकि, विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में माना गया था, लेकिन समन आदेश कानून की नजर में बुरा है क्योंकि अदालत ने संहिता की खंड 200 या 202 के तहत कोई जांच नहीं की थी ।इसलिए, 15.11.2019 दिनांकित समन आदेश को कानूनी रूप से स्थिर नहीं रह्द सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए। तदनुसार, आपराधिक विविध ।आवेदन सं। 2020 का 887 अनुमति के योग्य है।

<u>दिनांकित आदेश 14.01.2019</u>

57. 14.01.2019 पर, न्यायालय ने एफ. आर. पर विचार किया। विचार करने से पहले सूचना देने वाले को जानकारी दी जाती थी ।कुछ विवादित तथ्य हैं, अर्थात्:-

(i) मूल सूचना देने वाले को जानकारी नहीं दी गई थी।

(ii) सूचना देने वाले का बयान बिना किसी कानून के प्रावधान के दर्ज किया गया था।

(iii) अगर सूचना देने वाले का बयान दर्ज किया जाता है, तो उस पर ठीक से विचार नहीं किया जाता है।

(iv) अपने जवाबी शपथ पत्र में, राज्य ने कहा है कि कोई अभिभावक शिक्षक संघ नहीं था, इसलिए अभिभावक शिक्षक संघ को जानकारी देने का कोई सवाल ही नहीं था।

58. एफ. आर. पर विचार करते समय सूचना देने वाले का बयान दर्ज करना निश्चित रूप से कानून के किसी भी प्रावधान के बिना था ।तत्काल मामले में एफ. आर. पर विचार करने की पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से खराब थी।14.01.2019 पर, न्यायालय ने सूचना देने वाले के बयान पर विचार किया, जिसे न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया था और इस पर विस्तार से विचार किया गया था ।बयान दर्ज नहीं किया जा सका था ।इस तरह का बयान आदेश के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। यह 14.01.2019 दिनांकित आदेश को दूषित करता है।

59. याचिकाकर्ता की ओर से एक तर्क बहुत जोरदार ढंग से दिया गया है कि पीड़ित नोटिस जारी करना करने के लिए अदालत का कोई दायित्व नहीं था और उस उद्देश्य के लिए भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसले का संदर्भ दिया गया है।

60. यह सच है कि भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट घायल व्यक्ति या मृतक के किसी रिश्तेदार को एफ. आर. पर विचार करने के लिए निर्धारित सुनवाई का नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन तब संहिता के मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया था।तत्काल पॉक्सो अधिनियम के तहत भी मामला है।अब सवाल यह है:क्या एफ. आर. स्वीकार करने वाला <आई. डी. 1> दिनांकित आदेश कानून के अनुसार है; और क्या एफ. आर. को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था और संज्ञान लिया जाना चाहिए था या आगे की जांच का आदेश दिया जाना था।सूचना देने वाले का बयान दर्ज करके एक त्रुटि हुई थी और जैसा कि कहा गया है, यह आदेश को दूषित करने में योगदान देता है।

61. निस्संदेह, न्यायालय एफ. आर. पर विचार करते समय आई. ओ. की राय से निर्देशित नहीं होता है। जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री एफ. आर. के भाग्य का निर्णय लेने में न्यायालय का मार्गदर्शन करती है। यदि सामग्री से अपराध होने का पता चलता है, तो न्यायालय आई. ओ. द्वारा दी गई राय के बावजूद संज्ञान ले सकता है। इसी तरह, यदि जांच कानून के अनुसार नहीं की गई है या गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है या अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं, तो अदालत नए सिरे से जांच का आदेश दे सकती है।आखिरकार, जांच सच्चाई की खोज है।यह और कुछ नहीं बल्कि मामले की सच्चाई को अदालत के सामने लाना है।

62. विनय त्यागी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "निष्पक्ष और उचित जांच" की उपयोगिता पर चर्चा की और निर्णय के पैरा 48 में कहा गया है कि-

> "48. आपराधिक न्यायशास्त्र में "निष्पक्ष और उचित जांच" अभिव्यक्ति का उद्देश्य या महत्व अंततः क्या है?इसका दोहरा उद्देश्य है:सबसे पहले, जाँच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार होनी चाहिए; दूसरा, एक निष्पक्ष जाँच पर पूरा जोर सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष मामले की सच्चाई को सामने लाना होगा।एक बार निष्पक्ष जांच के ये दोहरे प्रतिमान संतुष्ट हो जाने के बाद, अदालत के लिए जांच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कम से कम होगी, इसे रद्द करने या इसे किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता बहुत कम होगी।कानून के अनुसार निष्पक्ष और जांच के माध्यम से सच्चाई को सामने लाना अनिवार्य रूप से एक अनुचित, दागी जांच या गलत निहितार्थ के मामलों के आधार को पीछे हटना देगा।इस प्रकार यह

कानून की अदालत के लिए जांच के भाग्य के बारे में एक विशिष्ट आदेश पारित करना अपरिहार्य है, जो उसकी राय में अनुचित, दागी और जांच के नियमों के तय किए गए सिद्धांतों का उल्लंघन है।"

63. पूजा पाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में[15] इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेशिका में मार्गदर्शक सितारे पर चर्चा की, जैसा कि नीचे दिया गया है:

"92. यह कि न्यायाधीश की नींव बनाने प्रतिपादित न्यायाधीशिक आदेशिका में सत्य की प्रमुखता मार्गदर्शक तारा है, इस न्यायाधीशालय द्वारा मारिया मार्गरिडा सिक्वेरा फर्नांडीस बनाम इरास्मो जैक डी सिक्वेरा [मारिया मार्गरिडा सिक्वेरा फर्नांडीस बनाम इरास्मो जैक डी सिक्वेरा, *(2012) 5* एस. सी. सी. *370:(2012) 3* एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 126]यह फैसला सुनाया गया था कि पूरी न्यायिक प्रणाली केवल वास्तविक सच्चाई को समझने और पता लगाने के लिए बनाई गई थी और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को इसकी खोज करने की यात्रा में खुद को गंभीरता से संलग्न करना होगा।इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चाई की खोज कानून का अधिदेश है और वास्तव में अदालतों का बाध्य कर्तव्य है, यह देखा गया कि न्यायाधीश प्रणाली तभी विश्वसनीयता प्राप्त करेगी जब लोग आश्वस्त होंगे कि न्यायाधीश सच्चाई की नींव पर आधारित है।अनुमोदन के साथ उल्लेख करते हुए, रितेश तिवारी बनाम U.P की स्थिति में किया गया खुलासा करने वाला अवलोकन। [रितेश तिवारी बनाम स्टेट ऑफ *U.P.*, (2010) *10 SCC* 677:(2010) *4* एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 315] कि प्रत्येक परीक्षण खोज की यात्रा है जिसमें सत्य खोज है, जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड [जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड, (1957) 2 क्यू. बी. 55 में लिखित लॉर्ड डेनिंग का निम्नलिखित अंश:(1957) *2* डब्ल्यूएलआर *760:(1957) 2* ऑल ईआर 155 (सीए)] पुष्टि में निकाला गया था:(मारिया मार्गारिडा मामला [मारिया मार्गारिडा सिक्वेरा फर्नांडीस बनाम इरास्मो जैक डी सिक्वेरा, *(2012) 5* एस. सी. सी. 370:(2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 126], एस. सी. सी पी.384, पैरा 39)

"39. ... '... न्यायाधीश अंधे को चित्रित करना बहुत अच्छा है, लेकिन वह अपनी आंखों के चारों ओर पट्टी के बिना बेहतर करती है।उसे वास्तव में पक्ष या पक्षपातपूर्ण के प्रति अंधा होना चाहिए, लेकिन यह देखने के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि सच्चाई किस रास्ते पर है।(जोन्स मामला [जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड, (1957) 2 क्यू. बी. 55:(1957) 2 डब्ल्यूएलआर 760:(1957) 2 ऑल ई. आर. 155 (सी. ए.)], क्यू. बी. पी. 64) ""

माननीय न्यायालय ने आगे कहा:

"87. कोई भी आपराधिक अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है, जो मानवाधिकारों के संरक्षक और संरक्षक और कानून के संरक्षक के रूप में राज्य पर अपनी पवित्र भूमिका की जिम्मेदारी का बर्खास्तगी करने के लिए एक भारी जिम्मेदारी डालता है और किसी भी चूक के लिए हमेशा कानून का पालन करने वाले नागरिकों के प्रति प्रतिबद्ध रूप से जवाबदेह होता है।आगे की जांच या पुनर्निवेश का निर्देश देने की संवैधानिक अदालतों की शक्ति न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का एक गतिशील घटक है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और हालांकि इसका उपयोग उचित सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और स्वयं लगाए गए संयम के साथ सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी संपूर्णता और विषय- वस्तु को किसी भी कानून द्वारा न तो प्रोत्साहित किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है।

88. आपराधिक न्यायशास्त्र में "निष्पक्ष और उचित जांच" अभिव्यक्ति इस न्यायालय द्वारा विनय त्यागी बनाम इरशाद अली [विनय त्यागी बनाम इरशाद अली, *(2013) 5* एस. सी. सी. 762 में अभिनिर्धारित की गई थी:(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 557] दो अनिवार्यताओं को शामिल करने के लिए; पहला, जांच निष्पक्ष, ईमानदार, न्यायपूर्ण और कानून के अनुसार होनी चाहिए; और दूसरा,

[15] (2016) 3 एससीसी 135

सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष मामले की सच्चाई को सामने लाने पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

64. निस्संदेह, जाँच वह संरचना है जिस पर मुकदमा आधारित है।निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित जाँच निष्पक्ष सुनवाई का सार है।यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की एक विशेषता है, जैसा कि विनुभाई हरिभाई मालवीय और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में देखा गया है।[16]..फैसले का पैरा 27 इस प्रकार है:

"27. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति बहुत व्यापक है, क्योंकि यह न्यायिक प्राधिकरण है जिसे संतुष्ट किया जाना चाहिए कि पुलिस द्वारा उचित जांच की जाती है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस द्वारा एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जाँच के अर्थ में एक "उचित जाँच" होती है-जिसकी निगरानी ऐसे मजिस्ट्रेट को करनी है-भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह आदेश देता है कि सभी आवश्यक शक्तियाँ, जो आकस्मिक या निहित भी हो सकती हैं, मजिस्ट्रेट के लिए एक उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें बिना किसी संदेह के, खंड 173 (2) के तहत उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की जाँच का आदेश शामिल होगा; और जब तक मुकदमा शुरू नहीं हो जाता, तब तक आपराधिक कार्यवाही के सभी चरणों में ऐसे मजिस्ट्रेट में कौन सी शक्ति सुनिश्चित करना जारी रहेगी।वास्तव में, शाब्दिक रूप से भी, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (1) में निर्दिष्ट "जांच", दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (1) में निर्दिष्ट "जांच" की परिभाषा के अनुसार, खंड 2 (एच) के तहत "जांच" की परिभाषा के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए साक्ष्य के संग्रह के लिए सभी कार्यवाही शामिल होगी; जिसमें निस्संदेह दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 173 (8) के तहत आगे की जांच के माध्यम से कार्यवाही शामिल होगी।

65. क्या जांच उचित रही है?क्या यह मामला आगे की जांच के लिए उपयुक्त है?यह सच है कि विरोध याचिका में डीडी ने आगे की जांच के लिए अनुरोध नहीं किया था।डीडी ने विरोध याचिका के माध्यम से दिनांकित <आईडी1> के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसके द्वारा एफआर को इस अनुरोध के साथ स्वीकार कर लिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है। 14.01.2019 दिनांकित आदेश को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब यह कानून के अनुसार न हो या केवल तभी माना जाए कि मजिस्ट्रेट को कोई अन्य आदेश पारित करना चाहिए था।अदालत के समक्ष अपनी याचिका में डीडी ने स्पष्ट रूप से मामले की आगे की जांच के लिए निर्देश देने की मांग की है।

66. तत्काल मामले में, शुरू से ही अपनाया गया पाठ्यक्रम कानून के अनुसार नहीं था। कथित तौर पर पी. टी. ए. द्वारा स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ यौन आक्रमण की शिकायत की गई थी। केस डायरी से पता चलता है कि शिक्षा विभाग और एस. डी. एम. द्वारा इसकी जांच की गई थी। एसएसपी, उधम सिंह नगर ने सर्कल अधिकारी, सितारगंज को निर्देश दिया

---

[16] (2019) 17 एससीसी 1

मामले में पूछताछ करना और आवश्यक कार्रवाई करना ।ऐसे मामलों में विभागीय जांच पर विचार करने का सवाल कुछ अजीब है।

67. यह पॉक्सो अधिनियम के खिलाफ एक अपराध था, एक ऐसा अधिनियम जो बच्चों को यौन अपराधों आदि से बचाने के लिए बनाया गया है। यह पाया गया कि कोई अभिभावक शिक्षक संघ नहीं था, लेकिन यह शुरू में प्रदान की गई जानकारी की उपयोगिता को भी कम नहीं करता है। आई. ओ. ने केस डायरी में लिखा है कि जब सूचना देने वाले की रिपोर्ट एसएसपी, उधम सिंह नगर द्वारा मामला दर्ज करने के लिए भेजी गई थी, तो यह निर्देश दिया गया था कि एक लिखित शिकायत प्राप्त की जा सकती है ।इसकी उपयोगिता क्या थी?एस. डी. एम. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संदर्भ केस डायरी में भी दिया गया है, जिसके अनुसार, पीड़ितों में से एक ने मामले का समर्थन किया था ।हालांकि, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट मामले का समर्थन नहीं करती है ।लेकिन, शुरुआत से इस पाठ्यक्रम को कैसे अपनाया गया?

68. यह न्यायालय इस तथ्य से सावधान है कि, केस डायरी का संदर्भ आम तौर पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जो आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत एफ. आर. की स्वीकृति को चुनौती देता है और एफ. आर. पर विचार करते समय अदालत के समक्ष उपलब्ध एकमात्र सामग्री आई. ओ. द्वारा एकत्र की गई सामग्री है, जिसे केस डायरी में जगह मिलती है ।इसलिए केस डायरी का संदर्भ दिया जा रहा है।

69. हस्तक्षेप मामले की रिपोर्ट संहिता की खंड 154 के तहत दर्ज की जाती है ।यदि मामला हस्तक्षेप अपराध का खुलासा करता है, तो क्या प्राथमिकी दर्ज किए बिना जांच का आदेश दिया जा सकता है?यह ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चर्चा का विषय रहा है।[17], और बिंदुओं पर सभी कानूनों पर चर्चा करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 120 में निष्कर्ष का सारांश दिया जैसा कि नीचे दिया गया है:

> "120. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं:
>
> **120.1.** संहिता की खंड 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि जानकारी किसी हस्तक्षेप अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

[17] (2014) 2 एससीसी 1

120.2. यदि प्राप्त जानकारी हस्तक्षेप अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि हस्तक्षेप अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

120.3. यदि जांच में किसी हस्तक्षेप अपराध का खुलासा होता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के समापन की प्रविष्टि की एक प्रति पहले सूचना देने वाले को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए।उसे शिकायत को बंद करने और आगे नहीं बढ़ने के कारणों का संक्षिप्त में खुलासा करना चाहिए।

120.4. यदि हस्तक्षेप अपराध का खुलासा किया जाता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं यदि उनके द्वारा प्राप्त जानकारी एक हस्तक्षेप अपराध का खुलासा करती है।

120.5. प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी हस्तक्षेप अपराध का खुलासा करती है।

120.6. किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जाँच की जानी है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

(a) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

(b) व्यावसायिक अपराध

(c) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

(d) भ्रष्टाचार के मामले

(e) जिन मामलों में आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी होती है, उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी।

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

120.7. अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारणों में प्रतिबिंबित होना चाहिए सामान्य डायरी प्रविष्टि।

120.8. चूंकि सामान्य डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरी एक पुलिस स्टेशन में प्राप्त सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि संज्ञेय अपराध से संबंधित सभी जानकारी, चाहे वह प्राथमिकी दर्ज करने के परिणामस्वरूप हो या जांच के लिए अग्रणी हो, उक्त डायरी में अनिवार्य और सावधानीपूर्वक प्रतिबिंबित होनी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने का निर्णय भी परिलक्षित होना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।"

70. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देश का एक नंगे अवलोकन यह आदेश देता है कि तत्काल मामले में कोई गुंजाइश नहीं थी

कोई भी प्रारंभिक जांच।शुरू में लिया गया पाठ्यक्रम गलत था।एस. एस. पी. उधम सिंह नागर के पास एक बोर्डिंग स्कूल के बच्चों पर यौन आक्रमण के अपराध का खुलासा करने वाली रिपोर्ट में जांच का निर्देश देने का कोई काम नहीं था।यह अपराध वास्तव में जघन्य था।इस तरह के अपराध का शिकार होने वाला व्यक्ति स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोल सकता था; जब रक्षक हमलावर बन जाता है, विशेष रूप से छात्रावास का, तो ऐसे पीड़ितों की दुर्दशा को समझा जा सकता है।यदि पीड़ितों ने सीधे मामले की सूचना नहीं दी थी, तो इसका मामले की जांच में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।इतना ही नहीं, पॉक्सो अधिनियम की खंड 19 में प्रावधान है कि जब भी ऐसे अपराधों की सूचना दी जाती है तो उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए।इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "अपराधों की रिपोर्टिंग
>
> (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति (बच्चे सहित), जिसे आशंका है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जिसे पता है कि ऐसा अपराध किया गया है, वह ऐसी जानकारी निम्नलिखित को प्रदान करेगा: -
> (a) विशेष किशोर पुलिस इकाई; या
> (b) स्थानीय पुलिस।
> (2) उप-धारा (1) के तहत दी गई प्रत्येक रिपोर्ट होगी -
> (a) एक प्रविष्टि संख्या अंकित की और लिखित रूप में दर्ज की गई;
> (b) सूचना देने वाले को पढ़ा जाए;
> (c) पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।
> (3) जहाँ उप-धारा (1) के तहत रिपोर्ट किसी बच्चे द्वारा दी जाती है, वहाँ उसे उप-धारा (2) के तहत सरल भाषा में दर्ज किया जाएगा ताकि बच्चा दर्ज की जा रही सामग्री को समझ सके।
> (4) यदि सामग्री उस भाषा में दर्ज की जा रही है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है या जहां भी इसे आवश्यक समझा जाता है, तो एक अनुवादक या दुभाषिया, जिसके पास ऐसी योग्यता, अनुभव है और ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जो निर्धारित किया जा सकता है, बच्चे को प्रदान किया जाएगा यदि वह इसे समझने में विफल रहता है।
> (5) जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि जिस बच्चे के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर बच्चे को आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती करने सहित ऐसी देखभाल और सुरक्षा देने की तत्काल व्यवस्था करेगी, जो निर्धारित की जाए।
> (6) विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस, बिना किसी अनावश्यक देरी के, लेकिन चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को या जहां कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं किया गया है, मामले की रिपोर्ट सत्र न्यायालय को करेगी, जिसमें बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता और इस संबंध में उठाए गए कदम शामिल हैं।
> (7) उप-खंड (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावना से जानकारी देने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक, कोई दायित्व नहीं लेगा।"

71. इसलिए, शुरू में पी. टी. ए. द्वारा कथित रूप से दी गई रिपोर्ट पर प्राथमिकी आर. दर्ज नहीं करना कानून के अनुसार नहीं था।एसएसपी ने

उधम सिंह नागर ने पहली बार में प्राथमिकी दर्ज नहीं करके कानून का उल्लंघन किया।जांच और रिपोर्ट का निर्देश कानून के अनुसार नहीं था।

72. इस न्यायालय ने कहा है कि एक बार एफ. आर. प्राप्त होने और सूचना देने वाले को सूचित किए जाने के बाद, सूचना देने वाले का बयान कानून के किसी भी प्रावधान के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता है।एफ. आर. पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा की गई यह एक और अवैधता थी।

73. तत्काल मामले में एफ. आर. इस आधार पर दायर किया गया है कि आई. ओ. को सबूत नहीं मिल सके।दिनांक 14.01.2019 के आदेश में, अदालत ने कहा है कि आई. ओ. ने इस आधार पर एफ. आर. दायर किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत प्राप्त नहीं किए जा सके।साक्षय एकत्र किए जाने थे।आई. ओ. वास्तव में इस साधारण कारण से ऐसा करने में विफल रहा कि सभी पीड़ितों की जांच नहीं की गई थी।जाँच रिपोर्ट में सूचना देने वाला स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि कुछ पीड़ित i.e हैं। तीन ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ यौन आक्रमण के मामले का समर्थन किया।हालांकि बाद में, जब संहिता की खंड 164 के तहत जांच की गई, तो उन्होंने मामले का समर्थन नहीं किया और अपने पहले के बयानों से पीछे हट गए।लेकिन, डीडी और दो और पीड़ित थे जिनका नाम सूचना देने वाले द्वारा की गई जांच के दौरान पीड़ितों में से एक ने लिया था।न तो उसकी और न ही अन्य पीड़ितों की जाँच के दौरान सूचना देने वाले या आई. ओ. द्वारा जाँच की गई थी। क्यों?एक पीड़ित का बयान भी पर्याप्त है।तत्काल मामले में पीड़ितों से पूछताछ की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।यह एक बड़ी चूक है।

74. तत्काल मामले में, जिसमें आरोप हैं कि स्कूल प्रबंधक ने छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों का यौन उत्पीड़न किया है, आई. ओ. को कुछ पीड़ितों के बयान दर्ज करने और दूसरों को छोड़ने का कोई विवेकाधिकार नहीं था।एक पीड़ित का बयान ही काफी है।

75. भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य कर दिया कि सूचना देने वाले को एफ. आर. नोटिस पर विचार करने से पहले दिया जाना चाहिए। लेकिन, पॉक्सो अधिनियम एक अलग अधिनियम है। यह एक विशेष अधिनियम है। इसकी खंड 25 (2) में यह अपेक्षा की गई है कि यदि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो संहिता की खंड 207 के तहत निर्दिष्ट सभी दस्तावेज -

बच्चों और उनके माता-पिता या उनके प्रतिनिधियों को प्रदान किया गया।खंड 25 इस प्रकार है:

> "मजिस्ट्रेट द्वारा एक बच्चे का बयान दर्ज करना।
>
> (1) यदि बच्चे का बयान खंड के तहत दर्ज किया जा रहा है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 (जिसे इसमें संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार, ऐसा बयान दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट, उसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद, बच्चे द्वारा बोले गए बयान को दर्ज करेगा:
>
> बशर्ते कि संहिता की खंड 164 की उप-खंड (1) के पहले परंतुक में निहित प्रावधान, जहां तक यह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति की अनुमति देता है, इस मामले में लागू नहीं होंगे।
>
> (2) मजिस्ट्रेट उस संहिता की खंड 173 के तहत पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने पर बच्चे और उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की खंड 207 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेज़ की एक प्रति प्रदान करेगा।"

76. जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक बार एफ. आर. दायर किए जाने के बाद, पॉक्सो अधिनियम की खंड 25 (2) को देखते हुए मजिस्ट्रेट संहिता की खंड 207 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रति बच्चे और उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को प्रदान करेगा।पॉक्सो अधिनियम की खंड 25 (2) में 'अंतिम रिपोर्ट' शब्दों का उपयोग किया गया है।कोड में कहीं भी एफ. आर. को परिभाषित नहीं किया गया है।पुलिस द्वारा जाँच के बाद संहिता की खंड 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसे पुलिस रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है।यदि पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि या तो कोई अपराध नहीं किया गया है या अपराधी का पता नहीं लगाया गया है, तो ऐसी पुलिस रिपोर्ट को 'अंतिम रिपोर्ट' के रूप में जाना जाता है।अभिनंदन झा (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "यह देखा जाएगा कि संहिता, इस प्रकार, 'आरोप पत्र' या 'अंतिम रिपोर्ट' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है।लेकिन नियमों और विनियमों वाली पुलिस नियमावली में यह समझा जाता है कि संहिता की खंड **170** के तहत दायर पुलिस की रिपोर्ट को 'आरोप पत्र' के रूप में संदर्भित किया जाता है।लेकिन खंड **169 i.e** के तहत भेजी गई रिपोर्टों के संबंध में। जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, तो इसे विभिन्न राज्यों में या तो 'निर्दिष्ट आरोप', 'अंतिम रिपोर्ट' या 'सारांश' कहा जाता है।"अदालत ने आगे एक सवाल उठाया कि" तब सवाल यह है कि जब मजिस्ट्रेट खंड **173** के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, तो स्थिति क्या है कि किसी आरोपी को मुकदमे के लिए भेजने का कोई मामला नहीं बनता है, जो रिपोर्ट, जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, सम्बंधित क्षेत्र में 'अंतिम रिपोर्ट' के रूप में बुलाई गई है?"

77. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पॉक्सो अधिनियम में 'पुलिस रिपोर्ट' और 'अंतिम रिपोर्ट' के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है।पॉक्सो अधिनियम की खंड 33 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान विशेष न्यायालय द्वारा शिकायत पर या 'पुलिस रिपोर्ट' पर लिया जा सकता है।हमने देखा है कि पॉक्सो अधिनियम की खंड 25 (2) में उपयोग किए गए शब्द 'अंतिम रिपोर्ट' हैं।पॉक्सो अधिनियम की खंड 31 में प्रावधान है कि संहिता के प्रावधान पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमे में लागू होंगे और विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा। मुकदमे के लिए मामले के समर्पण से पहले सत्र परीक्षणों में, संहिता की खंड 208 के तहत एक आरोपी को दस्तावेजों की प्रतियां दी जाती हैं।संहिता में सूचना देने वाले को प्रतियां देने का प्रावधान नहीं है।भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देना चाहिए और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।पॉक्सो अधिनियम उन मामलों में एक विशेष प्रावधान करता है जब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और जैसा कि कहा गया है, पॉक्सो अधिनियम की खंड 25 (2) के तहत ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट बच्चे और उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की खंड 207 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेज़ की एक प्रति प्रदान करने के लिए बाध्य है।यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यदि जांच के बाद बच्चे के लिए एफआर दायर किया जाता है, तो उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से सुना जाएगा।

78. सूचना देने वाले की दिनांकित आई. डी. 1 के आधार पर दर्ज की गई मामले की प्राथमिकी आर. में डी. डी. का नाम पीड़ित के रूप में दिखाया गया है।उसका नाम एक अन्य पीड़ित ने लिया था और अन्य पीड़ित भी हैं।लेकिन, डी. डी. को खंड के अनुसार दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे

पॉक्सो अधिनियम की धारा 25 (2)। इस आवश्यकता को भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के साथ पढ़ा जा सकता है।भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसला पॉक्सो अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया था। यह संहिता के प्रावधानों के संबंध में था।जब भगवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसला दिया गया था तो पॉक्सो अधिनियम अस्तित्व में नहीं था।इसलिए, तत्काल मामले में, अदालत के लिए यह अनिवार्य था कि वह डी. डी. और अन्य पीड़ितों को आई. ओ. द्वारा दिए गए सभी बयानों और निष्कर्ष या संहिता की खंड 164 के तहत बयान या संहिता की खंड 207 के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य दस्तावेज की आपूर्ति करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।एफआर को पॉक्सो अधिनियम की खंड 25 के प्रावधान की अवहेलना में स्वीकार किया गया था। यह पहले विविध मामले में पारित 14.01.2019 दिनांकित आदेश को भी दूषित करता है।

79. तत्काल मामले में, डीडी ने अपनी विरोध याचिका में कहा है कि जांच के दौरान, पुलिस ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन तथ्य यह है कि डीडी का बयान न तो जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था और न ही जांच अधिकारी द्वारा।क्यों?इस अदालत ने पहले ही कहा था कि डीडी और कुछ अन्य पीड़ितों के नाम के बावजूद, एक पीड़ित द्वारा खुलासा किया गया था; आईओ द्वारा उनकी जांच नहीं की गई थी। इससे जांच अधूरी हो जाती है।तत्काल मामले में जांच अधूरी थी।

<u>निष्कर्ष</u>

80. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि पहले विविध मामले में पारित 14.01.2019 का आदेश कानून के अनुसार नहीं है।इसे रद्द दिया जाना चाहिए था और मामले में आगे की जांच का आदेश दिया जाना चाहिए था।इसलिए 15.11.2019 का आक्षेपित आदेश कानून की नजर में बुरा है।

81. दिनांकित 15.11.2019 का आक्षेपित आदेश भी कानून के अनुसार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को संहिता की खंड 200 और 202 के तहत बिना किसी जांच के तलब किया गया है।इसे ध्यान में रखते हुए, 15.11.2019 दिनांकित आदेश को रद्द सकता है और दोनों याचिकाओं की अनुमति दी जा सकती है।

82. आपराधिक विविध।आवेदन सं। 2020 के 887 की अनुमति है।

83. आपराधिक विविध।आवेदन सं। 2021 का 31 भी अनुमत है।

84. दूसरे विविध मामले में पारित 15.11.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश को रद्द दिया गया है।

85. पहले विविध मामले में पारित 14.01.2019 दिनांकित आदेश जिसके द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की गई थी, को रद्द दिया गया है।

86. अंतिम रिपोर्ट सं। 2015 का 15 आई. ओ. द्वारा 2015 की एफ. आई. आर. संख्या 53 में भा.दं.सं. सी. की खंड 377,511 और पॉक्सो अधिनियम की खंड 9 के साथ 10, पुलिस स्टेशन पुलभट्टा, जिला उधम सिंह नगर के तहत प्रस्तुत किया गया है।जाँच अधिकारी को मामले की आगे की जाँच करने का निर्देश दिया जाता है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)
06.05.2021

जितेंद्र